भारत जोड़ो अभियान

राष्ट्रीय अधिवेशन का संकल्प मसौदा,

6 फरवरी 2023, नई दिल्ली

आज हम भारत के लोग, भारत के भविष्य की रक्षा के लिए एक सात साल की लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। आज हम एक आंदोलन शुरू करते हैं, **भारत जोड़ो अभियान**, जो हमारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की भावना को फिर से जगा सकता है, हमारे गणतंत्र एवं संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकता है, और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों एवं परम्पराओं को बचा सकता है ।

यह हमारे संविधान, हमारे राष्ट्रवाद, हमारी सभ्यता - वास्तव में, भारत के विचार पर हो रहे हमले के प्रतिरोध का एक आंदोलन है। यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक आंदोलन है जो सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगतिवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक क्षितिज का विस्तार कर सकता है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक वादे को सुदृढ़ करने के लिए एक विश्वसनीय आशा प्रदान करता है।

हम ऐसे नागरिकों का एक समुदाय हैं जिन्होंने विभिन्न जन आंदोलनों, स्वैच्छिक संगठनों और राजनीतिक संरचनाओं के साथ काम किया है। हममें से कई लोगों ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक ऐतिहासिक *भारत जोड़ो यात्रा* में भाग लिया है , जो यात्रा निराशा से आशावाद तक, चुप रहने से लेकर खुद को अभिव्यक्त करने तक, उंगली उठाने से लेकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने तक और अराजनैतिक रुख से लेकर नागरिकों के रूप में अपनी राजनीतिक भूमिका के स्पष्ट दावे तक चली।

इस यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हम सभी पर एक असाधारण जिम्मेदारी डालती है जिन्होंने इस यात्रा को अपने शरीर, मन या आत्मा से साथ दिया । हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, अपनी कड़ी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए और अपने संविधान की रक्षा के लिए अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज *भारत जोड़ो अभियान* शुरू करते हैं ।

भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारी विचारधारा को परिभाषित करती है। हमारे सभी नागरिकों के लिए “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, और आस्था की **स्वतंत्रता ;** स्थिति और अवसर की **समानता ;** और **बंधुत्व ”।**

संवैधानिक मूल्यों के प्रति यह प्रतिबद्धता कुछ ठोस गैर-परक्राम्य पदों पर जोर देती है जिसके लिए हम सभी खड़े हैं:

1. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और जो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और सब धर्मों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है;

2. जाति और लिंग आधारित असमानताओं और उत्पीड़न को पहचानने, निगरानी करने और बेअसर करने के लिए राज्य की नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए तत्पर है;

3. सहभागी, पारदर्शी और विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और सभी लोकतांत्रिक संस्थानों के स्वतंत्र संचालन को महत्व देता है;

4. एक कल्याणकारी राज्य जो लोगों को व्यापारिक लाभ से अंतिम व्यक्ति की भलाई को पहले रखता है और बिना सोचे-समझे निजीकरण और याराना पूँजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) का विरोध करता है;

5. ऐसी नीतियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर लोगों के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के विरोधाभास को संतुलित कर, परिवर्तन संकट से जूझने के लिए की हमारी जिम्मेदारी को पहचानती हैं;

6. सकारात्मक राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने पर केंद्रित है, विवादित मुद्दों पर में हमारे परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है, और पडोसी देशों एवं पूरे विश्व के साथ शांति चाहता है; और

7. हमारी सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत पर इसकी गौरवशाली बहुलता पर गर्व करता है और जो जाति, लिंग या इसके नाम पर किसी अन्य उत्पीड़न के उन्मूलन की जिम्मेदारी देता है।

ये मूल्य आज एक अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहे हैं। लगभग नौ वर्षों से, हमने अपने गणतंत्र को ईंट-दर-ईंट नष्ट होते देखा है। हमने लोकतांत्रिक तंत्र पर असभ्य बहुसंख्यकों का कब्जा, संस्थानों का विध्वंस, स्वतंत्र मीडिया का दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना, असहमति का अपराधीकरण, कानून के शासन का उल्लंघन और राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए राज्य और सड़क की शक्ति का उपयोग देखा है।

हमने धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक अल्पसंख्यकों को दूसरी श्रेणी की नागरिकता तक अवनति, उनके खिलाफ नफरत और कट्टरता के राजकीय प्रायोजित अभियान, सकारात्मक विचारधाराओं एवं कार्यक्रमों से पीछे हटना, जाति-आधारित उत्पीड़न और बहिष्कार, और नारी विरोधी पितृसत्तात्मक विचारधाराओं और प्रथाओं को खुले समर्थन को देखा है ।

हमने आम लोगों को आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और मंहगाई की मार झेलते हुए देखा है, जबकि मौजूदा शासन अपने अचानक अमीर यारों का पक्ष लेने, उनकी वित्तीय धोखाधड़ी का बचाव करने और राष्टीय संपत्ति बेचने में लगा हुआ है।

भटकाव, भटकाव और बंटवारा इस शासन की पसंदीदा राजनीतिक रणनीति है। हमने देखा है की मुख्यधारा मीडिया सरकार के लिए एक प्रचार भोंपू बजाने वाले पेशेवर बैंड में बदल गई है, जिसने वर्तमान शासन द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए आपराधिक उदासीनता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में पेशेवर अक्षमता और देश की सीमाओं की रक्षा करने में ढिलाई, को जनता के सामने नहीं दर्शाया |

इस दौरान हमने लोगों के आंदोलन को देखा और उससे प्रेरणा ली, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों को उलट दिया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ लोकप्रिय प्रतिरोध जिसने इसके कार्यान्वयन को रोक दिया और ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिसने इस सरकार को उन कानूनों को वापिस लेने के लिए मजबूर किया | हमने देखा कि राज्य स्तर पर धन, बाहुबल और मीडिया की ताकत के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के लिए कई चुनावी उलटफेर हुए हैं।

हमने सामाजिक प्रतिरोध के अनगिनत उदाहरण देखे हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत अभी भी जीवित है। हमने भारत जोड़ो यात्रा से सीखा है कि देश के बहुसंख्यक समुदाय ने सत्तारूढ़ व्यवस्था की विभाजनकारी राजनीति के आगे घुटने नहीं टेके हैं, कि कट्टरता और बड़े पैमाने पर झूठ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कि देश प्रेम की भाषा के लिए तरसता है और करुणा। हमने एक कथात्मक बदलाव और एक राजनीतिक परिवर्तन की संभावना देखी है।

आज हम चौराहे पर खड़े हैं। भारत की आजादी का 75 वां वर्ष नियति के साथ हमारे सामूहिक प्रयास का एक क्षण है। देश का भविष्य आशा और निराशा के बीच लटका हुआ है। केंद्र में भाजपा-आरएसएस के लिए 2024 में जीत का अर्थ संविधान का औपचारिक निरस्तीकरण और पुनर्लेखन हो सकता है। असहमति, विरोध, संघर्ष और प्रतिरोध के लिए जगह देने वाले कार्यात्मक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों से मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकना जरूरी है । इतिहास के इस मोड़ पर, हम नियमित विपक्षी राजनीति का अभ्यास नहीं कर सकते। हमें प्रतिरोध की सभी लोकतांत्रिक ताकतों को शामिल करने वाली एक समग्र एकता की आवश्यकता है। हमें विपक्षी पार्टियों की ताकत को जन आंदोलनों और जन संगठनों की ताकत से जोड़ना होगा ।

यद्यपि हम 2024 में शासन परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं, हमें साथ -साथ इन ताकतों के खिलाफ दीर्घकालिक वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्ष शुरू करना चाहिए।

यही कारण है कि हम **भारत जोड़ो अभियान** शुरू कर रहे हैं। हमारा तात्कालिक उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जनविरोधी और भारत विरोधी राजनीति की करारी हार सुनिश्चित करना है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सात वर्षीय भारत जोड़ो अभियान, जनवरी 2030 तक, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए। हम ऐसा करेंगे:

- संवैधानिक दृष्टि के अनुरूप हमारे समय के लिए भारत की दृष्टि को स्पष्ट करना;
- मुख्यधारा और वैकल्पिक मीडिया के माध्यम से इस दृष्टि को बढ़ाना;
- जमीन पर जनता की राय को आकार देने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण द्वारा भारत के संवैधानिक विचार में विश्वासियों का एक समुदाय बनाना;
- आंदोलनों का समर्थन करना और अभियान शुरू करना; और,
- गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव।

भाग II: संगठन

भारत जोड़ो अभियान एक समयबद्ध अभियान है जो संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों एवं परम्पराओं को बचाने एवं सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध नागरिक आज स्थापित कर रहे हैं । ***अभियान*** के कामकाज को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए: अत्यावश्यकता, चपलता, तेजी से निर्णय लेना; लचीलापन, प्रतिक्रिया और अनुकूलन में अनौपचारिकता; स्वायत्त स्व-निर्देशित कार्य को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना; सर्वसम्मति निर्माण और आपसी विश्वास के माध्यम से टीम वर्क; और, वित्त और कामकाज में स्वावलम्बन एवं पारदर्शिता। अभियान एक खुला, सार्वजनिक मंच बना रहेगा जो निम्नलिखित निकायों के माध्यम से कार्य करता है:

परामर्शदाता : अभियान को मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ और प्रतिष्ठित नागरिकों का एक समूह।

राष्ट्रीय/राज्य परिषद : प्रमुख नीतिगत निर्णयों के लिए एक व्यापक आधार वाली प्रतिनिधि संस्था।

राष्ट्रीय/राज्य कार्यकारी समूह : दिन-प्रतिदिन के निर्णयों के लिए एक छोटा कार्यकारी निकाय।

पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में सलाहकारों के पहले समूह, एक अनंतिम राष्ट्रीय परिषद [NC] और एक अनंतिम राष्ट्रीय कार्य समूह [NWG] को नामित किया जाएगा। नेकां राज्य स्तरीय निकायों के गठन के लिए बीजेए के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करेगी। राज्य परिषदें निर्वाचन क्षेत्र स्तर की टीमों को नामित करेंगी। अधिकांश राज्यों में राज्य स्तरीय सम्मेलनों के बाद एनसी और एनएसजी का पुनर्गठन किया जाएगा।

भाग III: कार्य योजना

अभियान विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित कार्यात्मक निकायों का निर्माण कर सकता है:

टीमें : सामरिक योजना और समन्वय के लिए नियमित कार्यात्मक दल ; विश्लेषिकी और डेटा प्रबंधन, संचार, प्रशिक्षण, वित्त और संचालन और सहायता आदि।

टास्क फोर्स : किसी विशिष्ट अभियान या घटना के लिए प्रोजेक्ट टीम।

सामूहिक: स्व-निर्देशित समूहों या व्यक्तियों की ढीली सहयोगी टीम।

सचिवालय: प्रत्येक टीम या टास्क फोर्स से जुड़ी स्थायी टीम।

अगले 15 महीनों के लिए, BJA उन राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करके अगले लोकसभा चुनावों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भाजपा-आरएसएस की राजनीति और विचारधारा के लिए प्रभावी प्रतिरोध की पेशकश करते हैं, बिना विपक्ष के मतभेदों में पड़े। हम निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव करते हैं:

A. ट्रुथ आर्मी (सत्य प्रचारक) : जो गलत सूचना और नफरत की पहचान करेगी और उसका मुकाबला करेगी, पहले से मौजूद आख्यानों का मुकाबला करेगी और सक्रिय रूप से वैकल्पिक आख्यान को बढ़ावा देगी। इसके लिए आवश्यकता होगी:

- वैकल्पिक आख्यान बनाने के लिए रणनीति टीम (15 मार्च तक, जिम्मेदार: NWG)
- कई भाषाओं और क्षेत्रों में सामग्री टीमें (राज्य सम्मेलन के एक महीने के भीतर, जिम्मेदार: राज्य डब्ल्यूजी)
- प्रत्येक लक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रसार केंद्र (राज्य सम्मेलन के 2 महीने के भीतर, जिम्मेदार: राज्य परिषद)

B. लक्षित निर्वाचन क्षेत्र अभियान : राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सक्रिय जमीनी स्तर का समर्थन प्रदान करना जो भाजपा और उसके सहयोगियों को हरा सकते हैं।

- प्रारंभिक ध्यान उन पांच राज्यों पर है जहां 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं: कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना
- लक्ष्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों [Target Assembly Constitunecy TAC टीएसी] जहां भाजपा छोटे अंतर से जीत या हार सकती है और मुख्य पार्टी जो इसका मुकाबला कर सकती है उसकी जेबीए एनालिटिक्स टीम पहचान करेगी ।

- प्रत्येक टीएसी में, राज्य परिषद भौतिक और मीडिया उपस्थिति स्थापित करेगी। प्रत्येक टीएसी में कम से कम 25 अभियात्रियों की एक टीम, जिनमें से 5 व्यक्ति योजना और समन्वय, कार्यक्रम और अभियान संगठन, संचार, वित्त और संचालन और प्रशिक्षण और डोर टू डोर अभियान के लिए जिम्मेदार होंगे। (जिम्मेदार - राज्य परिषद)
- प्रत्येक टीएसी टीम को प्रमुख स्थानीय मुद्दों और चुनाव तैयारी और प्रबंधन के तंत्र पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। (जिम्मेदार: राज्य प्रशिक्षण और संचार दल)
- लोक के लिए सभा चुनाव, लगभग 200 लक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का चयन (लगभग 1600 टीएसी) और 40,000 का प्रशिक्षण अभियात्री , जो 2 लाख प्रचारकों की भर्ती करेंगे|

C. आन्दोलन समर्थनः कुछ प्रमुख राष्ट्रीय और स्थानीय आन्दोलनों की पहचान करें जो लोगों के वास्तविक मुद्दों को उठाने में मदद कर रहे हैं और उनके संदेश को आगे ले जाने और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। राज्यों में कटौती करने वाले कुछ प्रमुख आंदोलनों के लिए कार्यबलों का गठन करें। (जिम्मेदार: एनसी और एससी)

D. विपक्षी एकता: जून 2023 तक सभी विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं के पास जाने और उनसे बात करने के लिए बुजुर्गों की एक समिति, उन्हें 2024 में भाजपा को हराने के लिए संयुक्त मोर्चे में काम करने के लिए प्रभावित करने के लिए। (जिम्मेदार: एनसी)

E. वित्त और संचालन टीम पहले 23 मार्च तक एक बहुआयामी फंड जुटाने की रणनीति विकसित करेगी और फिर अप्रैल से इस पर कार्रवाई करेगी। (जिम्मेदार: एनसी)। कई बीजेए समर्थन सेवा संगठनों को नामांकित करें। (जिम्मेदार: एनसी वित्त और संचालन टीम)